an>

title: Need to increase the ratio of re-finance amount of NABARD to co-operative Bank.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल के माध्यम से किसानों के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ।

नाबार्ड राज्य सरकार एवं जिला सहकारी बैंकों को रि-फाइनान्स करती है। वर्ष 2015-16 की नयी नीति के अनुसार पूर्व में 50 फीसदी राशि रि-फाइनान्स की जाती थी, उसे घटाकर 40 फीसदी किया गया है। मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात राज्य सहकारी बैंक ने अपनी सीमा के अनुसार 5027 करोड़ रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से नाबार्ड ने मात्र 3100 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया है। रि-फाइनान्स एंड का समय अल्पकाल के लिए होता है। किसानों को सात प्रतिशत के इंट्रेस्ट रेट से लगभग तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई घोषणाएँ की हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस ऋण को, जिसकी लिमिट 40 प्रतिशत कर दी गयी है, उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kirit P. Solanki.